रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल):

1997-98 **में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय**

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	कुल योजना परिव्यय (रु./करोड़)
1.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1340.00
2.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	144.00
3.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	16.00
4.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	0.05
5.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	3.00
6.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	9.00
7.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	1.00
8.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	1.00
	उर्वरक विभाग	
1.	फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	55.00
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन	41.00
3.	प्रोजेक्टस एंड डिलपमेंट इंडिया लिमिटेड	2.00
4	पायराइट्स, फास्फेट्स केमिकल्स लिमिटेड	6.00
5.	पारादीप फास्पेट्स लिमिटेड	49.50
6.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	37.00

Special Subsidy to Fermers of N.E. States

4135. SHRI W. ANCOU SINGH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Governments have given special subsidy to the farmers of the North East States;

(b) if so, how much subsidy has been given to each of the States;

(c) whether there is any arrangement for receiving the fertilisers in time in each State of North East region; and

(d) whether the subsidy to farmers is common all over India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZER: (DR. A.K. PATE): (a) and (b) There is no subsidy on fertilizers being given directly by the Government of India to the farmers including those in the North-Eastern States nor is it (subsidy) given to the States. The subsidy on fertilizers is indirect and is passed on through the manufactures/importers who are obliged to sell the fertilizers to farmers at the Maximum Retail Prices (MRP) fixed statutorily or otherwise by the Government.

(c) and (d) The States in the North-East have arrangements in place for receiving and marketing of fertilizers through the State agencies and/or private dealers. But in view of the difficulties experienced in the past in reaching fertilizers in time to these States due to inadequacy of rail network. Special Freight Reimbursement Scheme was introduced for urea in lieu of the Equated Freight Scheme w.e.f. 1.4.97. Under this Scheme actual costs of transportation are payable to the manufacturers/suppliers of urea. For decontrolled fertilizers, special dispensation has ben made w.e.f. 1.4.97 for meeting additional costs of transportation to these States under the Concession Scheme of Department of Agriculture & Cooperation.

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड को होने वाला घाटा

4136. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या सरायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड को निरंतर घाटा होने के क्या कारणहैं;

(ख) वर्ष 1995-96 से अब तक कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कम्पनी के प्रबंधन और कथित घाटे के लिए सरकारी तौर पर कोई अध्ययन किया है; और

(घ) सत्त घाटे के कारण अब तक कुल कतना वित्तीय नुकसान हुआ है और क्या मंत्री महोदय और सचिव महोदय ने प्रबंधन के साथ इस संबंध में कोई निचार-विमर्श किया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल): (क) से (घ) वर्ष 1995-96 से पारादीप फास्फेट लि. (पीपीएल) का वितीय कार्य निष्पांदन इस प्रकार रहा है:-

(रु./करोड़)

वर्ष	लाभ/हानी (+)/(-)
1995-96	(+) 2.24
1996-97	(-) 60.63
1997-98 (अनंतिं)	(-) 110.00

31.3.98 की स्थिति के अनुसार पी.पी.एल. को 261 करोड़ रुपये की संचयी हानी (अनंतिम) हुई थी। गत दो वर्षों के दौरान पी.पी.एल. को हुई हानी के निम्नलिकित कारण थे:-

कम उत्पादन के कारण

1996-97	डीएपी का अत्यधिक भण्डार एकत्र हो जाने के कारण डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) का कम उठान और डीएपी तथा बैंकिंग संयंत्र में अनुबन्ध श्रमिक समस्यायें।
1997-98	विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, रबी कौसम के जौरान डीएपी पर रियायत दर में कटौती और सरकारी ऋणों पर ब्याज भार

मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठकों में सचिव तथा रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा पी.पी.एल. के कार्यनिष्पादन का समय-समय पर विश्लेषण किया जाता है। विशेषज्ञ आघ्ययन के आधार पर कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा वितीय पूनर्गठन के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

Gas Cracker Project in Assam

4137. SHRI DRUPAD BORGOHAIN:
DR. ARUN KUMAR SARMA:
SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI PARAG CHALIHA:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the present status of the Gas Cracker Project in Assam;

(b) whether full project report of the proposed gas cracker is ready for execution;

(c) if so, details of the commission schedule and total outlay involved; and

(d) the reason for delay in starting the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (d) Reliance Assam Petrochemicals Ltd. (RAPL), a joint venture between Assam Industrial Development Corporation (AIDC) and Reliance Industries Ltd., (RIL) has Letter of Intent (LOI) for setting up the Gas Cracker Project in Assam.

Government of Assam have identified 1262 acres of land at Tengakhat of which 128 acres of land have already been handed over to RAPL. Ministry of Petroleum and Natural Gas has committed for supply of gas for producing 2 lakh TPA of Ethylene at a concessional price for a period of 15 years. Gas Supply Agreement between RAPL and Oil Indja Ltd. (OIL) is in advance stage of discussions. RAPL has identified 3.25 lakh TPA Naphtha from the refineries in Assam to be used as supplementary feedstock. Department of Chemicals and Petrochemicals has recommended to Ministry of Petroleum and Natural Gas for allocation of